साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 257 | जौनपुर, गुरूवार, 13 जून 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

विभव कुमार ने जमानत के लिए किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। मामला शुक्रवार 14 जून को सूचीबद्ध होने की संभावना है। इससे पहले 7 जून को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल के पूर्व पीए द्वारा दायर की गई यह दूसरी जमानत याचिका थी। इससे पहले 27 मई को उन्होंने अपनी पहली याचिका दायर की थी जिसे दिल्ली की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दिया था। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और 1 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

स्वाति मालीवाल मारपीट मामला

13 मई को हुई यह कथित घटना तब सामने आई जब मालीवाल ने कथित तौर पर सीएम आवास से पीसीआर कॉल कर अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया। बाद में उन्होंने कुछ दिनों बाद एक पुलिस शिकायत दर्ज की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार ने उन्हें दिल्ली के सीएम आवास पर सात से आठ बार थप्पड़ मारा, सीने, पेट और श्रोणि क्षेत्र पर लात मारी, जब वह सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए वहां गई थीं। जो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर थे।

संसद सत्र 24 जून से शुरू हो कर तीन जुलाई तक चलेगा – किरेन रीजीजू

नई दिल्ली, एजेंसी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा जिसमें नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। सत्र के पहले तीन दिन में नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे तथा सदन के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सत्र तीन जुलाई को संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले पांच वर्ष के लिए नई सरकार के कामकाज की रूपरेखा पेश करेंगी। रीजीजू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से तीन जुलाई 2024 तक नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ, अध्यक्ष के चुनाव, राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून को शुरू होगा और तीन जुलाई को संपन्न होगा। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे।

शिवराज सिंह चौहान के विरोध में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने बुधवार को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को आवंटित करने के एनडीए सरकार के फैसले का विरोध किया और जून 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में छह किसानों की हत्या के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। एक बयान में एसकेएम ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा दिए गए सी2 प्लस 50 प्रतिशत फॉर्मूले पर एमएसपी, व्यापक ऋण माफी और किसानों की आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ बड़े पैमाने पर संघर्ष में भाग लेने के दौरान किसानों की हत्या की गई। एसकेएम ने यह भी घोषणा की कि उसकी आम सभा की बैठक 10 जुलाई को दिल्ली में होगी जिसमें पूरे भारत से घटक किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे। एसकेएम ने कहा कि यह निर्णय 2014 और 2019 के पूर्व शासनकाल में भाजपा के पूर्ण बहुमत के साथ प्रदर्शित अहंकार और असंवेदनशीलता का प्रतीक है। इससे देश भर के किसानों और ग्रामीण लोगों में गुस्सा पैदा हुआ है। जून 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के एक समूह पर पुलिसकर्मियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों द्वारा की गई गोलीबारी में छह किसानों की मौत हो गई थी। एसकेएम, जिसने अब रद्द किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, ने कहा कि एनडीए सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में गंभीर कृषि संकट और किसानों की आत्महत्या या एमएसपी पर लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। पीएम किसान सम्मान निधि में ध्20,000 करोड़ का बकाया जारी करने के नाम पर जो प्रचार किया जा रहा है, वह एक मौजूदा योजना है जिसमें प्रति किसान परिवार को औसतन रू500 प्रति माह की राशि अपर्याप्त है।

गिरिराज सिंह को एनडीए सरकार में कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से लगातार दूसरी बार संसद भवन में पहुंचे गिरिराज सिंह को एनडीए सरकार में कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में उनके पास पशुधन और डेयरी मंत्रालय था। 2014 में उन्होंने बिहार की नवादा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। तो वहीं 2019 में सिंह ने जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और सीपीआई के युवा नेता कन्हैया कुमार को बेगूसराय से शिकस्त दी थी। गिरिराज सिंह का जन्म 8 सितंबर 1952 को बिहार के लखीसराय जिले के बरही गांव में हुआ था। वे एक साधारण किसान परिवार से आते हैं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों में ही हुई है। सिंह ने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी राजनीति और समाजशास्त्र में बचपन से ही रुचि होने के कारण उन्होंने राजनीतिक जीवन में अपना कदम रखा। गिरिराज सिंह ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के साथ की और पार्टी के संगठन को मजबूत करने और राज्य में भाजपा की विचारधारा को फैलाने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनकी निष्ठा और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें पार्टी के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। वे 2000 में लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से चुनकर बिहार की विधानसभा में पहुंचे। जहां उन्होंने 2014 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 2008 से 2010 के बीच गिरिराज सिंह नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी रहे। तो वहीं 2010 से 2013 तक उन्होंने राज्य सरकार में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भी संभाला था। गिरिराज सिंह अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते रहे हैं। पीएम पद के लिए मोदी का नाम गिरिराज सिंह ने 2013 में सार्वजनिक तौर पर आगे बढ़ाया था।

कांग्रेस का विदेश मंत्रालय से आग्रह, पीड़ितों के परिवारों तक हर संभव मदद जल्द पहुंचाएं

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने कुवैत में एक बड़ी इमारत में लगी आग में कई भारतीयों सहित कई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। साथ ही विदेश मंत्रालय से भारतीय पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। कुवैत में एक इमारत में लगी आग में लगभग 41 लोगों की मौत हुई है। जिसमें कई भारतीय भी शामिल हैं। अधिकारियों की मानें तो आग बुधवार तड़के कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत के मंगाफ इलाके में छह मंजिला इमारत की रसोई में लगी। इस इमारत में लगभग 160 लोग रहते है, जो कि इसी कंपनी के कर्मचारी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस दुर्घटना में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कुछ भारतीय भी शामिल हैं। इस घटना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कुवैत में हुई भयानक त्रासदी से दुखी हूं, जहां कई भारतीय मजदूरों की जान चली गई और कई के घायल होने की सूचना आ रही है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं। उन्होंने कहा, हम विदेश मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि पीड़ितों और उनके परिवारों को ईमानदारी से हर संभव सहायता प्रदान की जाए। कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी के सी वेणुगोपाल ने कहा, कुवैत में एक श्रमिक शिविर में आग लगने के कारण हमारे साथी भारतीय नागरिकों की जान जाने की खबर से बहुत दुख हुआ। दिवंगत आत्माओं के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। मैं विदेश मंत्रालय से इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों की तत्काल सहायता प्रदान की जाए। सभी पीड़ितों और उनके परिवारों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। वेणुगोपाल ने कहा कि यह घटना मध्य पूर्व में भारतीय मजदूरों के रहने की भयावह स्थिति की याद दिलाती है। वहीं केरल के अलप्पुझा से सांसद ने कहा, ष्सरकार को अपने समकक्षों के साथ मिलकर हमारे नागरिकों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

पानी की किल्लत के बीच आतिशी का बड़ा फैसला, क्विक रिस्पांस टीम तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी। एक तरफ जहां पूरे देश में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में लोग एमसीडी के पानी टैंकर पर निर्भर हो गए हैं। टैंकर से पानी लेने के लिए लोगों के बीच होड़ मची हुई है। ऐसे में पानी के संकट के बीच दिल्ली सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है। राजधानी में पानी के संकट को देखते हुए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बड़ा फैसला लिया है। पानी की समस्या से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम तैयारी की गई है। आतिशी ने एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि 30 मई से भीषण हुई गर्मी की स्थिति और पानी की बढ़ती मांग के मुद्दे पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 5 जून से प्रत्येक जोन में एडीएमध्एसडीएम स्तर के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, साथ ही तहसीलदारों और अन्य अधिकारियों की एक टीम भी तैनात की जाएगी। जो पानी के टैंकरों की व्यवस्था और पानी से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए क्विक रिस्पांस टीम के रूप में काम करेगी। जल मंत्री ने आगे मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर यह निर्देश दिया है कि ये टीमें प्रमुख पाइपलाइनों का निरीक्षण करेंगी। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पाइपलाइन में कोई रिसाव न हो और यदि कोई रिसाव है।

राजस्थान में भाजपा सरकार वादे के मुताबिक नहीं कर पा रही हैं काम – गहलोत

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर वादे के मुताबिक काम नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह ना तो वादे के मुताबिक पेट्रोल–डीजल की कीमतें गुजरात और हरियाणा के समान कर सकी है और ना ही महंगाई से राहत देने के लिए पहले से चल रहीं योजनाओं को मजबूत कर सकी है। श्री गहलोत ने सोशल मीडिया पर गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने कहा "हमारी सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाकर जनता को 10 राहत भरी योजनाएं दी थीं जिनमें 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री भी शामिल थी। इससे करीब 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं का बिल शून्य हो गया था और महंगाई से बड़ी राहत मिली थी। इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की गारंटी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विधानसभा चुनावों में देकर गए परन्तु राजस्थान सरकार इस गारंटी को झूठी साबित कर रही है। नए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं एवं पूर्व में रजिस्ट्रेशन ना करवा पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए नई सरकार ने कोई प्रक्रिया ही नहीं रखी है जिससे करीब 30 लाख उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। एक खबर को शेयर करते हुए कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार वादे के मुताबिक काम नहीं कर पा रही है।

100 दिनों के सरकार के एजेंडे पर सरकार का फोकस

नई दिल्ली, एजेंसी। मंत्रालयों के बंटवारे के अगले ही दिन मंगलवार को मोदी 3.0 के मंत्री मोर्चे पर जुट गए। भाजपा और सहयोगी दलों के अधिकांश मंत्रियों ने अपने–अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाल लिया। सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ देने को अपने सौ दिन के एजेंडे में प्रमुखता से रखा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों को इस एजेंडे पर फोकस करने को कहा है। वहीं, अमित शाह, एस. जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत ज्यादातर मंत्रियों ने अपना–अपना कार्यभाल संभालते हुए मोदी सरकार की 10 वर्ष की नीतियों की निरंतरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी जैसे कुछ मंत्री बुधवार या गुरुवार को कार्यभार संभालेंगे। पांच वर्ष बाद स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे जेपी नड्डा ने कार्यभार संभालने के बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान जैसी मोदी सरकार के प्राथमिकता वाले योजनाओं की समीक्षा की। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे की प्रमुख प्राथमिकताओं में नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यू–विन पोर्टल को पूरे देश में लागू करना भी शामिल है। इसी तरह अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना एवं प्रसारण दोनों मंत्रालयों का कार्यभार संभाल लिया। अपने पहले कार्यकाल में वैष्णव ने रेलवे के आधुनिकरण को नई दिशा दी थी। दूसरी बार पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद शिवराज सिह चौहान ने किसान कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताया।

अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में किसान सम्मान निधि की राशि जारी करके प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि कृषि और किसान सरकार के लिए काफी अहम हैं। महिला और बाल विकास विभाग का कार्यभार संभालने के बाद अन्नपूर्णा देवी ने नारी की नेतृत्वकारी भूमिका के स्वर्णिम सफर की शुरुआत का आह्वान किया। सहयोगी दलों के मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया।

पीयूष गोयल ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का संभाला कार्यभार

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त नेताओं में शुमार पीयूष गोयल इस बार मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से संसद भवन में पहुँचे हैं। मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकालों में गोयल की कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। एनडीए की सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया है। सरकार के पिछले शासनकाल में वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में कैबिनेट मंत्री बने थे। पीयूष गोयल का जन्म 13 जून 1964 को मुंबई (महाराष्ट्र) में हुआ था। उनके पिता वेद प्रकाश गोयल केन्द्रीय नौवहन मंत्री थे तथा दो दशकों से अधिक भाजपा के राष्ट्रीय ,कोषाध्यक्ष थे। उनकी माता चंद्रकांता गोयल मुंबई से महाराष्ट्र विधान सभा के लिए तीन बार चुनी गई थीं। गोयल का शानदार शैक्षणिक रिकार्ड रहा है, वे अखिल भारत में दूसरे रैंक धारित चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा मुंबई विश्वविद्यालय में लॉ में दूसरे रैंक धारक हैं। वे प्रख्यात निवेश बैंकर थे तथा प्रबंधन कार्यनीति एवं विकास पर प्रमुख कारपोरेटों को परामर्श दिया है। उन्होंने भारत के सबसे बडे वाणिज्यिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक आफ बडौदा के बोर्ड में भी कार्य किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में नदियों की इंटरलिंकिग के लिए कार्य बल में भी नामित किया गया था। अपने 35 वर्ष के लंबे राजनीतिक कैरियर के दौरान, गोयल ने विश्व की सबसे बडी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में विभिन्न स्तरों पर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हैं। वे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 2019 के भारतीय लोकसभा के आम चुनावों में वह मेनिफेस्टों और प्रचार समितियों के सदस्य थे। उन्होंने भारतीय लोकसभा के वर्ष 2014 आम चुनाव में भाजपा की सूचना संचार अभियान समिति का भी नेतृत्व किया। वे भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य रहे हैं तथा पूर्व में रेलवे एवं कोयला मंत्री थे।

अखिलेश ने करहल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा

लखनऊ, संवाददाता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे। उन्होंने करहल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इसके बाद उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना था तो उन्होंने करहल सीट छोड़ दी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के अनुसार यह इस्तीफा प्राप्त हो गया है। स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इससे पहले सपा के विधायक लालजी वर्मा भी इस्तीफा दे चुके हैं। लालजी वर्मा भी लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। इसके अलावा, फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि विधायक पद से आज इस्तीफा दे दिया हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मेरा प्रणाम, आपने मुझे लम्बे समय तक सेवा करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। अब सांसद होने के नाते आप सभी जनता की आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाऊंगा। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उनके चाचा विधायक शिवपाल सिंह यादव या फिर पीडीए के तीन विधायकों रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और कमाल अख्तर में से किसी एक को मिल सकता है।

संपादकीय

भाड़े का राज्य

लोकतंत्र और मानवाधिकारों को महत्व देने वाले सभी लोगों को पिछले महीने बहुत खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को जेल से रिहा करने का आदेश दिया और गौतम नवलखा को भी जमानत दे दी। हालांकि, मेरे लिए यह खुशी एक साथ हुए घटनाक्रम से पूरी तरह हैरान करने वाली थीय वह यह कि सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा से कहा कि वह पिछले महीनों के दौरान उनकी सुरक्षा पर हुए खर्च को कवर करने के लिए राज्य को 20 लाख रुपये का भुगतान करें, जब वह चिकित्सा आधार पर घर में नजरबंद थे। बेशक, यह राज्य के अभियोजकों द्वारा मांगी गई राशि से बहुत कम थीय लेकिन उनके द्वारा किसी भी मुआवजे का भुगतान किए जाने का विचार ही विचित्र है। चिकित्सा आधार पर घर में नजरबंद करना राज्य द्वारा कैदी पर किया गया कोई एहसान नहीं हैय इस पर अदालत में तीखे तरीके से बहस होती है और विशेषज्ञ चिकित्सा राय के आधार पर केवल तभी अनुमति दी जाती है जब इसे बिल्कुल आवश्यक माना जाता है। अगर यह एक एहसान होता और राज्य विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुआवजा चाहता, तो यह कमोडिटी एक्सचेंज के समान होतारू श्आप मुझे पैसे दें, मैं आपके लिए विशेष व्यवस्था करूंगाश्य यह फिर भी विचित्र होता, लेकिन कम से कम कमोडिटी एक्सचेंज के तर्क का हवाला तो दिया ही जा सकता था। लेकिन मेडिकल आधार पर घर में नजरबंद करना राज्य द्वारा किसी पर किया गया उपकार नहीं है। इसलिए ऐसे मामले में की गई विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए कैदी से मुआवजा मांगना पूरी तरह से अक्षम्य है। सिद्धांत रूप में यह किसी व्यक्ति को कैद करने और उसी व्यक्ति से उसे कैद करने पर हुए खर्च की मांग करने से अलग नहीं हैय मामले की विचित्रता तब और बढ़ जाती है जब हम यह विचार करते हैं कि उस व्यक्ति को दोषी भी नहीं ठहराया गया है, बल्कि वह केवल मुकदमे का इंतजार कर रहा है। यह राज्य द्वारा सड़क पर किसी भी व्यक्ति को उठाकर, उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में डालने और उस व्यक्ति से ही इस कारावास पर हुए खर्च की वसूली करने के बराबर है! यहां दो और सिद्धांत बिंदु ध्यान देने योग्य हैं। पहला, मेडिकल आधार पर घर में नजरबंद रहने की अवधि के दौरान की गई विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए किसी व्यक्ति से शुल्क लेना संविधान में निहित 'कानून के समक्ष समानता' के मूल सिद्धांत का उल्लंघन है। इसका मतलब यह है कि दो कैदियों के बीच जो एक ही तरह की परेशानी से पीड़ित हैं, उन्हें ऐसी छूट मिलनी चाहिए, जबकि अमीर व्यक्ति जो इसे वहन कर सकता है, उसे यह मिल जाएगी, जबकि गरीब व्यक्ति जो ऐसा नहीं कर सकता, उसे यह नहीं मिल पाएगीय इस प्रकार बाद वाले को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। निःसंदेह मुझे गरीब कैदियों के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में बताया जाएगा जो ऐसी स्थितियों का ख्याल रखती हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी कैदी को पूरी सहायता मिलेगीय इसलिए भेदभाव और कानून के समक्ष समानता का अभाव बना हुआ है। दूसरा, चिकित्सा आधार पर घर में नजरबंदी के दौरान कैदी से उसकी सुरक्षा पर होने वाले खर्च के लिए शुल्क लेने का विचार, जब वह इस तरह के खर्चों की राशि पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि वह यह तय नहीं करता है कि सुरक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, घोर अनुचित है। यह उस मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, अर्थात 'प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं'। नवलखा के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर कर की राशि को दो–तिहाई से अधिक कम कर दिया। लेकिन यह तथ्य कि वह ऐसा कर सकता है, लेवी की मनमानी को रेखांकित करता है। मुझे नहीं मालूम कि कैदियों को नजरबंद रखने के लिए की गई विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनसे पैसे वसूलने की प्रथा कब शुरू हुई। मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस समाजवादी थे और 1936 में भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। 1948 में कलकत्ता कांग्रेस के बाद पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया था, तब उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उस समय कम्युनिस्ट कैदियों द्वारा सामूहिक भूख हड़ताल की गई थी, जिसके दौरान मेरे पिता तीन सप्ताह से अधिक समय तक भूख हड़ताल पर रहे थेय जब उनकी हड़ताल नहीं टूट पाई और जबरन खिलाने से भी काम नहीं चला, तो उन्हें इस शर्त पर जेल से घर भेज दिया गया कि वे सप्ताह में एक बार स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि यह रियायत किस नियम के तहत आती थी, लेकिन जो भी थी, उन्हें राज्य को एक पैसा भी नहीं देना पड़ता थाय वे ऐसा कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता होने के कारण उन्होंने कभी कोई आय–अर्जन वाली नौकरी नहीं की थी। जाहिर है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद के भारतीय राज्य में वह भाड़े की नीचता नहीं थी, जो समकालीन भारतीय राज्य में है। समकालीन भारतीय राज्य एक सामान्य बुर्जुआ राज्य के सिद्धांतों का भी पालन नहीं करता है। जब सलमान रुश्दी की जान अयातुल्ला खुमैनी के फतवे के कारण खतरे में पड़ गई, तो उन्हें कई सालों तक ब्रिटिश सुरक्षा बलों द्वारा संरक्षित सुरक्षित घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन व्यवस्थाओं पर ब्रिटिश राज्य को कई सालों तक हर साल काफी पैसा खर्च करना पड़ा होगा लेकिन रुश्दी को ब्रिटिश राज्य को एक पैसा भी नहीं देना पड़ा।

बाजार तो ऐसे ही चलता है, जरूरी है दीर्घकालीन दृष्टिकोण

नारायण

शेयर बाजारों में निवेश करना कमजोर दिलवालों का काम नहीं है, खासकर तब, जब बाजार अस्थिर हो। जब बाजार एक ही दिन या छोटी अवधि में ऊपर–नीचे होता रहता है, तो इसका मतलब है कि बाजार अस्थिर है। जाहिर है, एक आम निवेशक इस अस्थिरता को चिंता का कारण मान सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारे दिल की धड़कन ऊपर–नीचे होती रहती है, जो हमें जीवित रखती है, उसी तरह शेयर बाजार के सूचकांक शेयर बाजार को गतिमान रखने के लिए ऊपर–नीचे होते रहते हैं। इस अर्थ में, यदि बाजार का सूचकांक सपाट यानी स्थिर है, तो इसका मतलब है कि यह यानी बाजार मरा हुआ है, ठीक उसी तरह, जैसे दिल की धड़कन रुकने पर कोई व्यक्ति मर जाता है। शेयर बाजार में उतार–चढ़ाव के कई कारक होते हैं, जिनमें स्थानीय एवं वैश्विक समाचार से लेकर राजनीतिक नतीजे, व्यापार चक्र और डर इत्यादि शामिल रहते हैं। फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनके कारण शेयर बाजार चरम स्थिति में पहुंच जाता है। विगत चार जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए थे, तब जिस तरह की चरम स्थितियां देखी गई थीं, वैसी घटना हाल के समय में वर्ष 2021 में कोविड लॉकडाउन की घोषणा के समय देखी गई थी। उस दिन यानी चार जून को, एस ऐंड पी बीएसई सेंसेक्स में 4,000 से अधिक अंकों और लगभग छह फीसदी की भारी गिरावट देखी गई, जो अभूतपूर्व थी। ऐसा लग रहा था, मानो घरेलू और विदेशी, दोनों निवेशक भारतीय बाजारों से बाहर निकलना चाहते थे। चुनाव परिणाम के दिन भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट पर बात करने से पहले हमें विगत 19 मई की ओर लौटना चाहिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलीविजन चौनल से बात करते हुए कहा था कि चार जून को शेयर बाजार रिकॉर्ड तोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही ऐसा कहा था, बल्कि लोकसभा चुनाव के विभिन्न चरणों के दौरान उनके मंत्रिमंडल के कई प्रमुख सदस्यों ने इस तरह की टिप्पणी की थी। सत्तारूढ़ पार्टी के इस आत्मविश्वास को निवेशकों ने बाजार में निवेश करने के संकेत के रूप में समझा। नतीजतन मई के अधिकांश दिनों में, चुनावों के अंतिम चरण तक बीएसई सेंसेक्स ज्यादातर दिनों में बढ़ता ही रहा। इसे इस बात का संकेत माना गया कि बाजार सरकार की वापसी और उसकी नीतियों की निरंतरता में यकीन रखती है। बाजार के लिए जनता के मूड से संकेत लेना और भी दिलचस्प हो गया, क्योंकि एक जून को आए एग्जिट पोल में भाजपा की स्पष्ट और बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई थी। स्वाभाविक रूप से तीन जून को जब बाजार खुले, तो बाजार में भारी खरीदारी देखी गई। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सेंसेक्स में 2,600 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल, तीन जून को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 6,851 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने, जिनमें बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और अन्य भारतीय संस्थान शामिल हैं, 1,914 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। हालांकि अगले ही दिन जब मतगणना शुरू हुई, तो चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुईं, खासकर शुरुआती रुझानों में। सरकार गठन को लेकर निवेशकों की चिंता के कारण शेयर बाजार के सेंसेक्स में दिन भर उतार–चढ़ाव देखा गया और यह 4,300 अंक से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ। विदेशी निवेशकों ने करीब 1.5 अरब डॉलर के भारतीय शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों ने भी 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली की। बहुत से ऐसे सट्टेबाज थे, जिन्होंने सिर्फ ट्रेंड्स और सुनी गई खबरों के आधार पर ही बाजार में अपना पैसा लगाया था। यह भी संभव है कि इनमें कुछ नए निवेशक भी हों, जो बाजार के जोखिमों को नहीं समझते हों और सिर्फ अटकलों पर ही भरोसा करते हों। उन्होंने भी पैसे गंवाए, क्योंकि उन्होंने बाजार में गिरावट शुरू होते ही डर के मारे अपने पैसे निकाल लिए। अब एक ही दिन में 30 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का आंकड़ा बताया जा रहा है। यह जरूरी नहीं कि इनमें से सारा पैसा निवेशकों का ही हो, क्योंकि नुकसान उठाने वालों में कई व्यापारी भी थे, जो बाजार के खिलाफ दांव लगाकर पैसे बनाने के लिए जाने जाते हैं। अन्य चर्चाओं के विपरीत, शेयर बाजार हर दिन को अलग–अलग तरह से देखता है, लेकिन यह भविष्य की संभावनाओं पर भी निगाहें रखता है। इसलिए बाजार की चाल से अवगत होने के कुछ ही दिनों के भीतर सेंसेक्स न केवल चार जून की गिरावट से उबर गया है, बल्कि यह तीन जून के उच्चतम स्तर को भी पार कर गया है। असल में इसने 10 जून को एक नई ऊंचाई को छुआ और उम्मीद है कि भविष्य में यह और आगे जाएगा। निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बाजार के दीर्घकालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखें और बाजार में निवेश करना जारी रखें। शेयर बाजार में अल्पावधि में उतार–चढ़ाव तो होंगे, लेकिन ये सभी निवेश का हिस्सा हैं। एक निवेशक के तौर पर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अल्पावधि में बाजार कैसे काम करता है।

आरएसएस से पूछ-परख नहीं, इसलिए बीजेपी को नहीं मिला बहुमत

ईश्वर

उत्तर प्रदेश में भाजपा को संघ से दूरी भारी पड़ गई। जिलों में न तो संघ और भाजपा ठश्रच की समन्वय समितियां दिखीं और न ही डैमेज कंट्रोल के लिए बैठकें हुईं। भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया। लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेटे रखा। लोकसभा चुनाव में करीब आधी सीटों तक सिमटने वाली भाजपा की हार के भले ही कई कारण गिनाए जा रहे हों, पर संघ से दूरी भी एक बड़ी वजह है। संभवतः यह पहला चुनाव है जिसमें भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया। लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेटे रखा। इसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। यह पहला चुनाव था जिसमें चुनावी प्रबंधन में संघ परिवार और भाजपा में दूरी दिखी। भाजपा ने किसी भी फैसले में उससे परामर्श करने तक की भी जरूरत नहीं समझी। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मौन साध रखा था। आमतौर पर चुनाव में जमीनी प्रबंधन में सहयोग करने वाले संघ के स्वयंसेवक इस चुनाव में शायद ही कहीं दिखे हों। जिलों में न तो संघ और भाजपा की समन्वय समितियां दिखीं और न ही डैमेज कंट्रोल के लिए छोटे–छोटे स्तर पर अमूमन होने वाली संघ परिवार की बैठकें होती नजर आईं। कम मतदान पर लोगों को घर से निकालने वाले समूह भी इस चुनाव में कहीं नहीं दिखे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो संघ ने चुनाव से किनारा कर लिया। संघ से जुड़े कुछ वर्तमान, पूर्व पदाधिकारियों व प्रचारकों के अनुसार इसकी मुख्य वजह भाजपा के एकांगी निर्णय और संघ परिवार के संगठनों के साथ संवादहीनता रही। माना जाता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बयान "भाजपा अब पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गई है। इसलिए उसे अब संघ के समर्थन की जरूरत नहीं है" ने भी स्वयंसेवकों उदासीन कर दिया। संघ के एक पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि संघ अचानक तटस्थ होकर नहीं बैठा था। संघ से जुड़े सूत्रों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले परिणामों के बाद आत्ममुग्धता से लबरेज भाजपा ने अपने सियासी फैसलों में संघ परिवार को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। भाजपा ने जब संघ परिवार की सलाह की अनदेखी कर एक के बाद एक कई ऐसे फैसले कर डाले, जिनसे संगठन की साख और सरोकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना लाजिमी था, इसलिए संघ ने भी अपनी भूमिका समेट ली। अयोध्या में श्रीरामलला के प्राण–प्रतिष्ठा को लेकर भी कुछ मतभेद उभरे। स्वा "ईं म्समबजपवदे 2024 बताया जाता है कि संघ ने कौशांबी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, बस्ती, अंबेडकरनगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ सहित प्रदेश की लगभग 25 सीटों के उम्मीदवारों पर असहमति जताई थी। साथ ही बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के लोगों को भाजपा में शामिल करने पर भी नाराजगी वयक्त की थी। जानकारी के मुताबिक, संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से कहा

था कि दूसरे दलों के दागी और अलोकप्रिय चेहरों को शामिल करना उचित नहीं है। इससे गुटबाजी बढ़ रही है। साथ ही संगठन की साख पर भी सवाल उठ रहा है। पर, उसकी सलाह नहीं मानी गई। लिहाजा संघ उदासीन हो गया। चुनाव की घोषणा के एक साल पहले ही संघ परिवार ने अपने वैचारिक कार्यक्रम के तहत जनता से संवाद शुरू कर दिया था। घोषणा होने तक हर लोकसभा क्षेत्रों में एक–एक लाख बैठकें हो चुकी थीं।

नागरिकों ने मोदी 3.0 को संदेश दिया

विनोद

चिलचिलाती गर्मी और तीखे चुनावी विश्लेषण के इस मौसम में, एक महत्वपूर्ण संदेश है – वास्तविकता को समझें। 2024 के आम चुनाव के नतीजों को कई तरह से देखा और समझा जा सकता है, लेकिन अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि लाखों भारतीय मतदाता चाहते हैं कि सरकार आम लोगों की वास्तविक जिंदगी पर तुरंत ध्यान दे। संक्षेप में, दूर के अतीत या मृतकों के बजाय वर्तमान पर। लोग मुगलों की बजाय पैसे, अपनी अल्प

आय के बारे में अधिक चिंतित हैं, जिन्होंने 16वीं सदी की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था, और जिन्हें भाजपा नेताओं द्वारा बार–बार मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में संदर्भित किया गया है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जीत हासिल की है। 73 वर्षीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन एक सिकुड़े हुए प्रभामंडल के साथ। इस बार, कोई शानदार जीत नहीं हुई। इसके बजाय, उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत विपक्ष है। विपक्षी भारत ब्लॉक ने सामूहिक रूप से 232 सीटें हासिल कीं। भाजपा ने 240 सीटें हासिल कीं, जो अपने दम पर सरकार बनाने के लिए आवश्यक 272 सीटों के बहुमत से कम है। मोदी 3.0 एनडीए के प्रमुख सहयोगियों जैसे तेलुगू देशम पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) के साथ–साथ छोटे समूहों पर निर्भर है। यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि लोगों ने जिस तरह से वोट किया, उसका कारण क्या है। हालांकि, ग्राउंड रिपोर्ट से कुछ बातें स्पष्ट हैं। नई सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय अभी भी धार्मिक रूप से बहुत अधिक हैं। हालांकि, लाखों लोगों को यह एहसास होने लगा है कि केवल धार्मिक उत्साह से बिलों का भुगतान नहीं होता हैय हिंदू–मुस्लिम ध्रुवीकरण से पेट नहीं भरता है। आखिरकार, सभी को नौकरी की जरूरत है। कल्याणकारी लाभ – नकद हस्तांतरण, सब्सिडी वाली रसोई गैस, पाइप से पानी और मुफ्त अनाज – स्वागत योग्य हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं हैं। कई विश्लेषक इस बात से हैरान हैं कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की हार हुई, जिसमें अयोध्या का मंदिर शहर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वस्त बाबरी मस्जिद पर बने राम मंदिर के उद्घाटन में भाग लिया था। कई लोग पूछते हैं कि मतदाता उस पार्टी को कैसे खारिज कर सकते हैं जिसने भगवान के जन्मस्थान माने जाने वाले स्थान पर राम मंदिर बनाने का अपना पुराना वादा पूरा किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दलित अवधेश प्रसाद ने मौजूदा भाजपा सांसद लल्लू सिंह को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसका मतलब यह नहीं है कि मतदाता आस्था या भगवान राम को त्याग रहे हैं। लेकिन यह आर्थिक वास्तविकताओं के बारे में उनकी बढ़ती चिंता को दर्शाता है। जो लोग ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए भारत में ग्रामीण संकट और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की कहानी कोई नई बात नहीं है। लगातार अलर्ट जारी किए गए हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी पट्टी में कई "पेपर लीक" नौकरी के संकट और सामाजिक सुरक्षा के बिना देश में बढ़ती हताशा की ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, इस साल की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नौकरी के लिए लगभग 1,000 उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा से ठीक पहले लीक हुए प्रश्नपत्र को देखने के लिए गुड़गांव के एक रिसॉर्ट में जमा हो गए थे। जमीन से मिली जानकारी बताती है कि फैजाबाद और अयोध्या शहरों में, कई लोगों ने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और मंदिर अर्थव्यवस्था के बढ़ने की संभावनाओं के कारण भाजपा को वोट देने की बात कही, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने संकट और विस्थापन की बात कही। उसी निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में माहौल बहुत ज्यादा उदास था। यहाँ, मतदाताओं, जिनमें ज्यादातर पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक शामिल हैं, को लगा कि उनके मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उन्हें मंदिर अर्थव्यवस्था और शहर के पुनर्विकास से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। पिछले दिसंबर में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया, ष्स्थानीय लोग जिनकी संपत्ति पुनर्विकास में ध्वस्त कर दी गई, वे जमीन की बढ़ती कीमतों और कम मुआवजे के कारण विस्थापित महसूस कर रहे हैं। और शहर के अनुमानित 3,50,000 के बड़े मुस्लिम समुदाय में से कुछ ने कहा कि उन्हें उछाल का फायदा नहीं मिल रहा है।ष जो हमें आज भारत में एक अहम मुद्दे पर ले आता है। भारत कई अरबपतियों के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो सकता है। लेकिन यह एक बहुत ही असमान समाज बना हुआ है, जहाँ लाखों लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन इसका फायदा सभी को नहीं मिला है। बढ़ती जीडीपी के साथ–साथ, घरेलू कर्ज बढ़ रहा है और घरेलू बचत घट रही है। लगभग 800 मिलियन भारतीय सरकार की मुफ्त खाद्यान्न योजना पर निर्भर हैं। भारत में, ग्रामीण संकट और नौकरियों के संकट के साथ–साथ लग्जरी क्रांति की गाथा सामने आ रही है। फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड हर्मीस ने हाल ही में मुंबई में देश में अपना तीसरा रिटेल स्टोर लॉन्च किया हैय लग्जरी अपार्टमेंट की मांग बढ़ रही है। लग्जरी कार और एसयूवी की बिक्री के मामले में भी यही स्थिति है। लेकिन ग्लैमर और चमक–दमक से परे एक और भी गहरा सच छिपा है। लाखों लोग, खास तौर पर गांवों और शहरी झुग्गियों में, अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

संसद में दागी नेताओं की संख्या बढ़ना चिन्ताजनक

ललित

देश में 18वीं लोकसभा चुनी जा चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और रिकॉर्ड संख्या में मतदाता होने के गर्व करने वाली स्थितियां हैं वहीं चिन्ता जनक, विचलित एवं परेशान करने वाली स्थितियां भी हैं। खबर आई है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचने वाले 543 सांसदों में 46 फीसदी आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं जो पिछली बार से तीन प्रतिशत अधिक है। भारतीय राजनीति में आपराधिक छवि वाले या किसी अपराध के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जाने एवं उन्हें राष्ट्र–निर्माण की जिम्मेदारी दिया जाना–हर नागरिक के माथे पर चिंता की लकीर लाने वाली है। क्या इस स्थिति में देश की लोकतांत्रिक शुचिता एवं पवित्रता की रक्षा हो पाएगी? क्या हम आदर्श एवं मूल्यपरक समाज बना पाएंगे? क्या ये दागदार नेता एवं जन–प्रतिनिधि कालांतर हमारी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मसलों का विश्लेषण करने वाली सचेतक संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 में चुने गये सांसदों में जहां 233 यानी 43 फीसदी ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की थी, वहीं अठाहरवीं लोकसभा के लिये चुने गए 251 सांसदों ने आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है। जो कुल संख्या का 46 फीसदी बैठती है। आज भारत की आजादी के अमृतकाल का एक बड़ा प्रश्न है भारत की राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का। यह बेवजह नहीं है कि देशभर में अपराधी तत्त्वों के राजनीति में बढ़ते दखल ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि अपहरण के आरोपी अदालत में पेश होने की जगह मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच जाते हैं। अरविन्द केजरीवाल जैसे नेता आम चुनाव में कहते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट दें ताकि मैं जेल जाने से बच जाऊं। हम ऐसे चरित्रहीन एवं अपराधी तत्वों को जिम्मेदारी के पद देकर कैसे सुशासन एवं ईमानदार व्यवस्था स्थापित करेंगे? कैसे आम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे? कैसे संसद में दागियों के पहुंचने के लिये द्वार बंद होंगे? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की सजग पहल पर ही वर्ष 2020 से सभी राजनीतिक दल लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करने लगे है। निश्चित ही इस आदेश का मकसद देश की राजनीति को आपराधिक छवि वाले नेताओं से मुक्त करना ही था। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की प्राथमिकता जीतने वाले उम्मीदवार थे, अब चाहे उनका आपराधिक रिकॉर्ड ही क्यों न हो। बड़ा प्रश्न है कि आखिर राजनीति में तब कौन आदर्श उपस्थित करेगा? क्या हो गया उन लोगों को जिन्होंने सदैव ही हर कुर्बानी करके आदर्श उपस्थित किया। लाखों के लिए अनुकरणीय बने, आदर्श बने। चाहे आजादी की लड़ाई हो, देश की सुरक्षा हो, धर्म की सुरक्षा हो, अपने वचन की रक्षा हो अथवा अपनी संस्कृति और अस्मिता की सुरक्षा का प्रश्न हो, उन्होंने फर्ज और वचन निभाने के लिए अपना सब कुछ होम दिया था। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, दुर्गादास, छत्रसाल, शिवाजी जैसे वीरों ने अपनी तथा अपने परिवार की सुख–सुविधा को गौण कर बड़ी कुर्बानी दी थी। गुरु गोविन्दसिंह ने अपने दोनों पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया और पन्नाधाय ने अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों का तो मन्दिर बनना चाहिए। इनके मन्दिर नहीं बने, पर लोगों के सिर श्रद्धा से झुकते हैं, इनका नाम आते ही। लेकिन आज जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय जीवन और सोच विकृत हुए हैं, हमारी राजनीति स्वार्थी एवं संकीर्ण बनी है, हमारा व्यवहार झूठा हुआ है, चेहरों से ज्यादा नकाबें ओढ़ रखी हैं, उसने हमारे सभी मूल्यों को धराशायी कर दिया। राष्ट्र के करोड़ों निवासी देश के भविष्य को लेकर चिन्ता और ऊहापोह में हैं। वक्त आ गया है जब देश की संस्कृति, गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कुछ शिखर के व्यक्तियों को भागीरथी प्रयास करना होगा। दिशाशून्य हुए नेतृत्व वर्ग के सामने नया मापदण्ड रखना होगा। अगर किसी हत्या, अपहरण या अन्य संगीन अपराधों में कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसे राजनीतिक बता कर संरक्षण देने की कोशिश या राजनीतिक लाभ उठाने की कुचेष्टा पर विराम लगाना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त राजनीति को सदैव प्राथमिकता दी लेकिन चुनाव जीतने के रण में वे भी अपराधी राजनेताओं को प्रश्रय देते हुए दिखे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने ही दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। जो राजनीतिक दलों की कथनी और करनी के भारी अंतर को ही उजागर करता है। सवाल है कि देश के लिये नीति निर्धारण करने वाले ऐसे दागी लोग हमारे भाग्यविधाता बने रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद हमारी कानून–व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? क्या होगा हमारे समाज व व्यवस्था का भविष्य? क्यों तमाम आदर्शों की बात करने वाले और दूसरे दलों के नेताओं की कारगुजारियों पर सवाल उठाने वाले नेता राजनीति को अपराधियों के वर्चस्व से मुक्त कराने की ईमानदार पहल नहीं करते? क्यों सभी राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र में शुचिता एवं पवित्रता के लिये सहमति नहीं बनाते? निश्चित रूप से यदि समय रहते इस दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं होती तो आने वाले वर्षों में दागियों का यह प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जाएगा। इसके साथ ही बड़ा संकट यह भी है कि देश के निचले सदन में येन–केन–प्रकारेण करोड़पति बने नेताओं का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। इस बार संसद में चुनकर आए सांसदों में 504 करोड़पति हैं। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि अपनी मेहनत की कमाई से जीवनयापन करने वाला आम आदमी कभी सांसद बनने की बात सोच सकता है? दागी एवं अपराधी राजनेता लोकतंत्र की एक बड़ी विडम्बना एवं विसंगति बनते जा रहे हैं। बात लोकसभा की ही नहीं है, विभिन्न राज्यों की सरकारों में भी कैसा विरोधाभास एवं विसंगति है कि एक अपराध छवि वाला नेता कानून मंत्री बन जाता है।

कार्यालय ग्राम पंचायत रीठी, विकास खण्ड–सिकरारा,जौनपुर

पत्रांक– मेमो/ग्रा0पं0म0/ दिनांक 12.06.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त/15वां केन्द्रीय वित्त आयोग/ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए निम्निलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.06.2024 से 18.06.2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपराह्न दो बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सीलबन्द निविदा जमा कर सकते है जो दिनांक 19.06.2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष सुबह 10:00 बजे खोली जायेगी। निविदा फार्म पैड पर होगी।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	मात्रा	दर
1	ईंट 150 एम0एम0 प्रथम श्रेणी/एस.ओ.बी. ईट	प्रति हजार	
2	सीमेंट	प्रति बैग	
3	मोरंग बालू, महीन बालू, गंगा बालू	प्रति घन मी0	
4	स्टोन ब्लास्ट, डाला गिट्टी, पत्थर गिट्टी 20 एम.एम. से 53 एम.एम. तक ईट गिट्टी 20 एम.एम./42एम.एम.	प्रति घन मी0	
5	सरिया विभिन्न साइज	प्रति कुन्तल	
6	करकर/एसबेस्टर सीट,पैनल आयरन, समरसेबुल, बोरिंग प्लेटफार्म सहित	प्रति नग	
7	पैर्क्स ब्लाक ईट/इण्टरलाकिंग ईट/जागजेडा इण्टरलाकिंग ईट	प्रति हजार	
8	सोलर लाईट/विद्युत सामग्री/स्ट्रीट लाईट/हाइमास्क सोलर लाईट	प्रति नग	
9	शौचालय निर्माण सामग्री/पंचायत भवन निर्माण सामग्री		
10	ह्यूम पाइप 150एम.एम. 300एम.एम. 350एम.एम. 600एम.एम. 800एम.एम. NP3	प्रति मी0	
11	ढ़क्कनदार नाली निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री आवश्यकतानुसार		
12	गिट्टी की भराई, समतलीकरण का कार्य	प्रति घन मी0	
13	सफाईकर्मी स्वच्छता किट/सेनेटाइजर,डस्टबीन सहित अन्य संबंधित सामग्री	प्रति नग	
14	कटीला तार एवं ईगल/प्रिकास्ट कंकरीट बेंच	प्रति नग	
15	जिम से संबंधित सामग्री/इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री/रिबोर	प्रति नग	
16	मैदान के सुन्दरीकरण हेतु घास	प्रति धन मी0	
17	चूना, पेन्ट इत्यादि	प्रति नग	
18	वाल पेटिंग व प्रचार–प्रसार	प्रति वर्ग मी0	
19	विडियो कैमरा, दिशासूचक बोर्ड/पब्लिक अड्रेस सिस्टम,स्कूल के लिए डेक्स व बेंच।	प्रति नग	
20	गौशाला में चूना–चोकर, भूसा, मनरेगा पार्क में खेलकूद, जिम, झूला व अन्य सामग्री।		
21	हैण्डपम्प की निष्प्रयोज्य सामग्री की खुली नीलामी		

प्रतिबन्ध एवं शर्तें– सामग्री की मात्रा कार्य स्वीकृत होने के बाद निर्धारित की जायेगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नहीं। सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि से स्वीकृत दर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा 50 रू0 के स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड भरना अनिवार्य होगा तदोपरान्त आपूर्ति किया जायेगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का सेल टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तथा आयकरदाता हो प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. के स्वीकृत दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा में की जानी अनिवार्य होगी। सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की दशा में भुगतान की धनराशि नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में चिह्नित होगा।

प्रधान — ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव
चन्द्रावती — राजकुमार पाण्डेय

कार्यालय ग्राम पंचायत फूलपुर, विकास खण्ड–सिकरारा,जौनपुर

पत्रांक– मेमो/ग्रा0पं0म0/ दिनांक 12.06.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त/15वां केन्द्रीय वित्त आयोग/ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए निम्निलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 16.06.2024 से 21.06.2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपराह्न दो बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सीलबन्द निविदा जमा कर सकते है जो दिनांक 22.06.2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष सुबह 10:00 बजे खोली जायेगी। निविदा फार्म पैड पर होगी।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	मात्रा	दर
1	ईंट 150 एम0एम0 प्रथम श्रेणी/एस.ओ.बी. ईट	प्रति हजार	
2	सीमेंट	प्रति बैग	
3	मोरंग बालू, महीन बालू, गंगा बालू	प्रति घन मी0	
4	स्टोन ब्लास्ट, डाला गिट्टी, पत्थर गिट्टी 20 एम.एम. से 53 एम.एम. तक ईट गिट्टी 20 एम.एम./42एम.एम.	प्रति घन मी0	
5	सरिया विभिन्न साइज	प्रति कुन्तल	
6	करकर/एसबेस्टर सीट,पैनल आयरन, समरसेबुल, बोरिंग प्लेटफार्म सहित	प्रति नग	
7	पैर्क्स ब्लाक ईट/इण्टरलाकिंग ईट/जागजेडा इण्टरलाकिंग ईट	प्रति हजार	
8	सोलर लाईट/विद्युत सामग्री/स्ट्रीट लाईट/हाइमास्क सोलर लाईट	प्रति नग	
9	शौचालय निर्माण सामग्री/पंचायत भवन निर्माण सामग्री		
10	ह्यूम पाइप 150एम.एम. 300एम.एम. 350एम.एम. 600एम.एम. 800एम.एम. NP3	प्रति मी0	
11	ढ़क्कनदार नाली निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री आवश्यकतानुसार		
12	गिट्टी की भराई, समतलीकरण का कार्य	प्रति घन मी0	
13	सफाईकर्मी स्वच्छता किट/सेनेटाइजर,डस्टबीन सहित अन्य संबंधित सामग्री	प्रति नग	
14	कटीला तार एवं ईगल/प्रिकास्ट कंकरीट बेंच	प्रति नग	
15	जिम से संबंधित सामग्री/इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री/रिबोर	प्रति नग	
16	मैदान के सुन्दरीकरण हेतु घास	प्रति धन मी0	
17	चूना, पेन्ट इत्यादि	प्रति नग	
18	वाल पेटिंग व प्रचार–प्रसार	प्रति वर्ग मी0	
19	विडियो कैमरा, दिशासूचक बोर्ड/पब्लिक अड्रेस सिस्टम,स्कूल के लिए डेक्स व बेंच।	प्रति नग	
20	गौशाला में चूना–चोकर, भूसा, मनरेगा पार्क में खेलकूद, जिम, झूला व अन्य सामग्री।		
21	हैण्डपम्प की निष्प्रयोज्य सामग्री की खुली नीलामी		

प्रतिबन्ध एवं शर्तें– सामग्री की मात्रा कार्य स्वीकृत होने के बाद निर्धारित की जायेगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नहीं। सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि से स्वीकृत दर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा 50 रू0 के स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड भरना अनिवार्य होगा तदोपरान्त आपूर्ति किया जायेगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का सेल टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तथा आयकरदाता हो प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. के स्वीकृत दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा में की जानी अनिवार्य होगी। सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की दशा में भुगतान की धनराशि नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में चिह्नित होगा।

प्रधान — ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव
सभाजीत यादव — विवेकानन्द यादव

कार्यालय ग्राम पंचायत नेवढ़िया, विकास खण्ड–सिकरारा,जौनपुर

पत्रांक– मेमो/ग्रा0पं0म0/ दिनांक 12.06.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त/15वां केन्द्रीय वित्त आयोग/ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए निम्निलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.06.2024 से 18.06.2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपराह्न दो बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सीलबन्द निविदा जमा कर सकते है जो दिनांक 19.06.2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह् 04:00 बजे खोली जायेगी। निविदा फार्म पैड पर होगी।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	मात्रा	दर
1	ईंट 150 एम0एम0 प्रथम श्रेणी/एस.ओ.बी. ईट	प्रति हजार	
2	सीमेंट	प्रति बैग	
3	मोरंग बालू, महीन बालू, गंगा बालू	प्रति घन मी0	
4	स्टोन ब्लास्ट, डाला गिट्टी, पत्थर गिट्टी 20 एम.एम. से 53 एम.एम. तक ईट गिट्टी 20 एम.एम./42एम.एम.	प्रति घन मी0	
5	सरिया विभिन्न साइज	प्रति कुन्तल	
6	करकर/एसबेस्टर सीट,पैनल आयरन, समरसेबुल, बोरिंग प्लेटफार्म सहित	प्रति नग	
7	पैर्क्स ब्लाक ईट/इण्टरलाकिंग ईट/जागजेडा इण्टरलाकिंग ईट	प्रति हजार	
8	सोलर लाईट/विद्युत सामग्री/स्ट्रीट लाईट/हाइमास्क सोलर लाईट	प्रति नग	
9	शौचालय निर्माण सामग्री/पंचायत भवन निर्माण सामग्री		
10	ह्यूम पाइप 150एम.एम. 300एम.एम. 350एम.एम. 600एम.एम. 800एम.एम. NP3	प्रति मी0	
11	ढ़क्कनदार नाली निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री आवश्यकतानुसार		
12	गिट्टी की भराई, समतलीकरण का कार्य	प्रति घन मी0	
13	सफाईकर्मी स्वच्छता किट/सेनेटाइजर,डस्टबीन सहित अन्य संबंधित सामग्री	प्रति नग	
14	कटीला तार एवं ईगल/प्रिकास्ट कंकरीट बेंच	प्रति नग	
15	जिम से संबंधित सामग्री/इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री/रिबोर	प्रति नग	
16	मैदान के सुन्दरीकरण हेतु घास	प्रति धन मी0	
17	चूना, पेन्ट इत्यादि	प्रति नग	
18	वाल पेटिंग व प्रचार–प्रसार	प्रति वर्ग मी0	
19	विडियो कैमरा, दिशासूचक बोर्ड/पब्लिक अड्रेस सिस्टम,स्कूल के लिए डेक्स व बेंच।	प्रति नग	
20	गौशाला में चूना–चोकर, भूसा, मनरेगा पार्क में खेलकूद, जिम, झूला व अन्य सामग्री।		
21	हैण्डपम्प की निष्प्रयोज्य सामग्री की खुली नीलामी		

प्रतिबन्ध एवं शर्तें– सामग्री की मात्रा कार्य स्वीकृत होने के बाद निर्धारित की जायेगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नहीं। सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि से स्वीकृत दर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा 50 रू0 के स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड भरना अनिवार्य होगा तदोपरान्त आपूर्ति किया जायेगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का सेल टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तथा आयकरदाता हो प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. के स्वीकृत दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा में की जानी अनिवार्य होगी। सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की दशा में भुगतान की धनराशि नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में चिह्नित होगा।

प्रधान — ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव
राजपती यादव — राजकुमार पाण्डेय

जौनपुर में एसपी ने तीन थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर के एसपी डॉ0 अजय पाल शर्मा ने जनपद के तीन थाना प्रभारियों को कार्यों में लापरवाही बरतने, घटनाओं का खुलासा न कर पाने तथा आम जनता के साथ उचित व्यवहार न रखने के आरोप में लाइन हाजिर किया।

एसपी डॉ0 अजय पाल शर्मा ने थाना प्रभारी सरायख्वाजा राजेश कुमार मिश्र, थाना प्रभारी मीरगंज देवानंद रजक, थाना प्रभारी सुजानगंज महेश पाल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। वही हाल ही में स्वाट टीम के विवेक तिवारी को

प्रिंस सिंह के एनकाउंटर किए जाने में बेहतरीन प्रदर्शन पर सुजानगंज थाने का थाना प्रभारी नियुक्त कर दिया है।

एस ओ जी से रमेश कुमार को थानाध्यक्ष मीरगंज व विवेचना सेल से अमित कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक सरायख्वाजा नियुक्त किया।

एसपी द्वारा तीन थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किए जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ।

डीएम व एसपी ने शांति समिति की बैठक कर, अधिकारीयों को दिए निर्देश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाईरूपुलिस अधीक्षक

जौनपुर। जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉंदड़ की अध्यक्षता में व पुलिस अधीक्षक डॉ0 अजय पाल शर्मा की उपस्थिति में जिला शांति समिति की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई।बैठक में आगामी बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण वातावरण में भाईचारा के साथ मनाये जाने की अपील की गयी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया कि खुले में कुर्बानी न करें और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न दें।

नमाज के लिए निर्धारित स्थान पर ही नमाज अदा करें! नमाज स्थल के आस–पास बेतरतीब वाहन न खड़ा करें।

साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थो को निर्धारित स्थल पर निस्तारित कराये।

एक्सईएन विद्युत को निर्देशित किया कि त्यौहार के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनी रहे।

ईदगाह के समीप की सड़क को ठीक करने के निर्देश एक्सईएन जलनिगम को दिया गया।

एक्सईएन पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया कि सड़के गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, जिससे लोगो को आवागमन में कोई असुविधा न हो।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जगहों पर खराब पेयजल की समस्या है वहां पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए समस्या का निस्तारण कराये।

नगर पालिका द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 1533 जारी किया गया है जिसमें नगर पालिका से सम्बन्धित शहर में साफ–सफाई, सीवर, पेयजल आदि से जुड़ी समस्याओं से सम्बन्धित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जिलाधिकारी ने अपर पुलिस अधीक्षक शहर बृजेश कुमार को निर्देशित किया कि सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़े होने वाले पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाए। जिन जगहों पर सड़क अतिक्रमण की समस्याएं अधिक है। वहां पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट कर लोगों को गाड़ियों को उचित जगह खड़े करने के लिए जागरूक किया जाए।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी प्रकार की समस्या को तुरंत प्रशासन को सूचित करने के लिए कहा ताकि समय रहते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा सके। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान, मुख्य राजस्व अधिकारी गणेश प्रसाद, उपजिलाधिकारी सदर पवन सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 लक्ष्मी सिंह, क्षेत्राधिकारीगण, शान्ति समिति के सदस्यगण सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता मिला अधेड़ का शव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। मड़ियाहूँ नगर के मिर्दहा मोहल्ले में गुरुवार की सुबह अपने ही मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ का फांसी से लटकता शव पाये जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाही में जुटी रही।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मोहल्ला निवासी मुमताज उर्फ झगडु 50 वर्ष अपने पुराने घर से 500 मीटर दूर नई बस्ती मिर्दहा में बने पाही के कमरे पर सोने के लिए प्रतिदिन जाते थे। पत्नी जमीला खातून के अनुसार बुधवार की रात वे खाना खाकर पाही पर सोने के लिए चले गये।

सुबह जब पाही से आने में देर हुई तो पत्नी जमीला खातून मौके पर पहुंची। बाहर से गेट के जाल में हाथ डालकर अंदर से बंद सिटकनी को खोल कर कमरे में पहुंची तो देखा कि मुमताज का शव गाटर के चूल्ले से रस्सी के सहारे जमीन तक लटक रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी रही। मृतक की पत्नी जमीला खातून ने बताया कि घर में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। पति ने फांसी क्यों लगाया यह समझ नहीं पा रही हूं।

आईटीआई का अनुदेशक निलंबित, प्रैक्टिकल में ज्यादा अंक देने के एवज में छात्रों से मांग रहा था पैसे

आगरा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के आगरा में राजकीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीई) बल्केश्वर में छात्रों से प्रैक्टिकल में ज्यादा अंक देने के एवज में रुपये मांगने वाले अनुदेशक

को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें संयुक्त निदेशक आईटीआई कानपुर से संबद्ध कर दिया गया है। साथ ही दंड निर्धारित करने के लिए संयुक्त निदेशक अलीगढ़ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। आईटीआई बल्केश्वर में अनुदेशक वर्कशाप कैलकुलेशन एंड साइंस विवेक लवानिया के दो ऑडियो वायरल हुए थे। इनमें वे मनमाफिक अंक दिलाने के लिए 6000 रुपये प्रति छात्र की रिश्वत मांग रहे थे। इसका एक छात्र ने ऑडियो बना लिया। यह ऑडियो संस्थान के शिक्षकों के ग्रुप में वायरल हुआ। पीड़ित छात्रों ने इसकी लिखित शिकायत प्रधानाचार्य मान सिंह भारती से की। मंडलीय संयुक्त निदेशक आईटीआई योगेंद्र सिंह ने भी प्रकरण की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी के सामने भी छात्रों ने अपनी समस्या दोहराई और बताया कि अनुदेशक विवेक लवानिया पहले भी छात्रों से रुपये की मांग कर चुके हैं। उनके पूर्व में छात्रों से लिए गए पेटीएम के स्क्रीन शॉट भी उपलब्ध करवाए गए। दोनों ही जांच कमेटियों की रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए। निदेशक आईटीआई कुणाल सिल्कू ने लवानिया को निलंबित कर दिया। निलंबन की अवधि में इस दौरान व संयुक्त निदेशक कानपुर मंडल से संबद्ध रहेंगे। अनुदेशक विवेक लवानिया की शिकायत मिली थी।

अकेले रह रही वृद्धा की मौत, बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में नवाबगंज के विष्णुपुरी में अकेले रहने वाली वृद्धा की घर में कुर्सी पर बैठकर पूजा करते समय मौत हो गई। मंगलवार को घर से बदबू आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर दी। दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव चार दिन पुराना बताया जा रहा है। विष्णुपुरी में रहने वाली अविवाहित कामिनी गुप्ता उर्फ रानी दीदी (65) घर में अकेली रहती थी। मंगलवार को उनके घर से बदबू आने पर सामने रहने वाले शेखर जायसवाल की पत्नी तनुजा ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा को तनुजा ने बताया कि कामिनी के घर का दरवाजा तीन–चार दिनों से खुला नहीं है। दरवाजा खटखटाने पर कोई हलचल नहीं हुई तो पुलिस ने कामिनी के काकादेव निवासी उनके भतीजे मनीष गुप्ता को मौके पर बुलाया। इसके बाद वीडियोग्राफी कराते हुए लोहे और लकड़ी के दरवाजे को तोड़ा और अंदर दाखिल हुए तो कामिनी गुप्ता मंदिर के सामने कुर्सी पर मृत अवस्था में बैठी हुई थी। देखने से लग रहा था कि उनका शव करीब 3–4 दिन पुराना है।

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

फोरेंसिक टीम के जांच करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक होने की मौत की आशंका जताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि कामिनी के बेंगलुरु में रहने वाले भाई को जानकारी दे दी गई है। बुधवार तक उनके कानपुर आने की उम्मीद है। उसके आने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी के मायके जाने से क्षुब्ध पति ने की आत्महत्या

फर्रुखाबाद, संवाददाता। फर्रुखाबाद जिले में पत्नी के मायके जाने से क्षुब्ध पति ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच कर शव का पोस्टमार्टम कराया। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला बीबीगंज निवासी लालू (35) मजदूरी करके परिवार की गुजर बसर करता था। 10 दिन पहले लालू का पत्नी राधा से विवाद हो गया। पत्नी राधा बच्चे खुशी व करन सहित छह माह की बेटी को लेकर मायके चली गई थी। इसके बाद से लालू परेशान चल रहा था। रात को लालू खाना खाने के बाद कमरे में सोने चला गया। लगभग 11 बजे मां मुन्नी देवी लालू के कमरे में गई। उसने लालू को दुपट्टे से कमरे के कुंडे में फंदे पर लटका देखा। मां मुन्नी देवी के चीखने पर पुत्र सोनू, निर्मल, दीपक, विशाल आ गए। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के बाद शव को फंदे से उतारा। पुलिस ने आत्महत्या के कारण के बारे में पूछा। मां मुन्नी देवी ने बताया कि 10 दिन पहले हुए विवाद के बाद बहू मायके चली गई थी। उसके बाद से लालू परेशान चल रहा था। जानकारी होने पर पत्नी राधा बच्चों सहित ससुराल आ गई। उसका रो–रो कर हाल बेहाल हो गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम में लालू की मौत फांसी लगने से दम घुटने के कारण हुई।

एसआईटी ने खंगाले रजिस्टर, कर्मचारियों से की पूछताछ, एक पूर्व डीआईओएस तलब

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में नौ फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति कराने के मामले की तह तक जाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने एक पूर्व डीआईओएस को नोटिस भेजकर बुधवार को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। इससे पहले एसआईटी ने मंगलवार को डीआईओएस और जिला परियोजना अधिकारी शिक्षा अभियान (रमसा) कार्यालय पहुंचकर छानबीन की। टीम ने दोनों दफ्तरों में शासन और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आने वाली ई–मेल को रिसीव करने और फिर अफसरों तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया को समझा। रजिस्टर भी चेक किए। एसआईटी को कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज से भर्ती के संबंध में भेजी गई फर्जी ई–मेल रमसा कार्यालय में रिसीव हुई थी। इसके बाद तत्कालीन डीआईओएस दफ्तर को भेजी गई थी। मामले से जुड़े रजिस्टर भी एसआईटी ने कब्जे में लिए हैं। एसआईटी प्रभारी एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार ने बताया कि पूर्व डीआईओएस मन्नीलाल को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। फर्जी भर्ती प्रकरण के दौरान मन्नीलाल की तैनाती यहीं थी। कुछ लिपिकों को भी बुलाया गया है। बता दें इससे पहले एसआईटी डीआईओएस कार्यालय के लिपिक सुनील कुमार, सेवानिवृत लिपिक राकेश से भी पूछताछ कर चुकी है। एसीपी व उनकी टीम सबसे पहले चुन्नीगंज स्थित डीआईओएस कार्यालय पहुंची। पूछताछ और छानबीन के बाद यहां से 150 मीटर दूर स्थित रमसा कार्यालय गई। यहां पता चला कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज से भेजी गई ई–मेल रमसा कार्यालय में रिसीव की गई थी। डीआईओएस को भेजी गई ई–मेल यहां क्यों रिसीव की गई, क्या तत्कालीन डीआईओएस के आदेश पर ऐसा किया गया, इस बारे में लिपिकों से पूछा गया। डीआईओएस कार्यालय के अरुण कुमार, शिल्पा, उत्तम व रमसा के एकाउंटेंट सुशील समेत 10 लोगों से पूछताछ हुई। एक अधिकारी ने बताया कि डीआईओएस ने मेल की कॉपी शिल्पा को दी थी, उनके आदेश के बाद ही नियुक्ति वाली ई–मेल की रजिस्टर में एंट्री की गई थी। अब तक की जांच में डीआईओएस कार्यालय की लापरवाही सामने आई है।

मामले में अब तक क्या?

इंटर कॉलेजों में लेक्चरर पद पर हुई नौ फर्जी शिक्षक भर्ती मामले में कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस प्रकरण की विवेचना के लिए एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी अब तक मास्टरमाइंड पिता–पुत्र समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

ट्रक का कट लगने से लोडर पलटा, नौ महिलाओं समेत दस लोग घायल

इटावा, संवाददाता। इटावा जिले में सैफई की तरफ से आ रहे लोडर में ट्रक ने कट मार दिया। लोडर अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में गिर गया। हादसे में लोडर सवार 10 लोग घायल हो गए। घायलों में नौ महिलाएं हैं। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। फिरोजबाद जिले के सिरसागंज थाना के नगला नैनसुख सीगेमई गांव के रहने वाले 14 लोग लोडर पर सवार होकर बलरई क्षेत्र के कोकावली के लिए निकले थे। कोकावली में रिश्तेदार दिलीप कुमार के घर शोकसभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बुधवार सुबह आठ बजे लोडर सैफई मोड़ पर पहुंचा, तभी आगरा की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने कट मार दिया। जिससे लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया।

हादसे में अखिलेश (50) पत्नी मोहर सिंह, सरिता देवी (52) पत्नी श्यामवीर सिंह, मीना देवी (45) पत्नी मानसिंह, जशोदा देवी (60) पत्नी वेद पाल सिंह, ओमश्री (46) पत्नी लायक सिंह, राम धनी (60) पत्नी मलखान, ब्रजेश देवी (55) पत्नी कोमल सिंह, हरि सिंह (64), शरला देवी (32) पत्नी राहुल, मिथलेश (55) पत्नी मुलायम सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

हादसे के बाद स्थानीय लोग व राहगीरों ने पलटे लोडर को सीधा कर घायलों को बाहर निकाला। घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भिजवाया। गंभीर घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया।

नाम बदलकर और धर्म छिपाकर युवक ने की दोस्ती, पांच वर्ष तक युवती से करता रहा दुष्कर्म

मेरठ, संवाददाता। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से नाम बदलकर दोस्ती करने के बाद दूसरे समुदाय के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाकर पांच साल से वह दुष्कर्म करता रहा। अब मामला परिजनों तक पहुंचा तो थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। युवती ने मंगलवार को थाने पर तहरीर दी। इसमें बताया कि वह नोएडा से एमबीए कर रही है और वहीं पर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। पहले वह परतापुर स्थित एक ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी करती थी। यहां उसकी मुलाकात दूसरे समुदाय के युवक से हुई थी।आरोप है कि युवक ने नाम बदलकर उसे गुमराह किया।

झांसे में लेकर दोस्ती की। पांच साल पहले जन्मदिन पर उसके साथ संबंध बनाए। इसका अश्लील वीडियो बनाया। परिजनों को बताने पर जान के मारने की धमकी दी। आरोप है कि युवक ब्लैकमेल कर उससे लगातार दुष्कर्म करता रहा है। दो महीने पूर्व भी आरोपी तमंचे के बल पर उसे जबरन गाड़ी में डालकर ले गया था। अब युवती ने परिजनों को इस घटना के बारे में बताया। मामले में मंगलवार को भाजपा नेता अंकित चौधरी के साथ पीड़ित परिजन थाने पहुंचे और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी विष्णु कौशिक का कहना है की तहरीर मिल गई है। आरोपी के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

डाक्टर–संचालक का मेल–अल्ट्रासाउंड में कमीशन का खेल, प्रसूताओं और मरीजों को भेजा जाता है निजी सेंटर

बांदा, संवाददाता। बांदा जिले में चिकित्सक और निजी सेंटर संचालकों की गठजोड़ से अल्ट्रासाउंड कराने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को खुलेआम लूटने का काम किया जा रहा है। इस बात की भनक अस्पताल के जिम्मेदारों को भी है, लेकिन कोई भी इस गोरखधंधे की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आलम यह है कि महिला अस्पताल से चिकित्सक मरीज के साथ महिला कर्मी को साथ भेजकर निजी सेंटर में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसके एवज में संबंधित चिकित्सक को निजी सेंटर संचालक से कमीशन के तौर पर मोटी रकम दी जाती है। जिला महिला अस्पताल में यह गोरखधंधा काफी समय से चल रहा है। इससे वहां तैनात चिकित्सक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। वहां पहुंचने वाली प्रसूताओं को बरगलाकर अपने एक नुमाइंदे के साथ प्राइवेट सेंटरों में भेजा जाता है। मालूम हो कि जिला पुरुष अस्पताल में निशुल्क अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। अगर वहां से प्रसूता अल्ट्रासाउंड कराने के बाद रिपोर्ट लेकर महिला अस्पताल के चिकित्सक के पास जाती है, तो रिपोर्ट सही न होने या फिर अन्य कारण बताकर उन्हें निजी सेंटर में जाकर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मजबूर किया जाता है।

अल्ट्रासाउंड कराने के नाम पर 700 रुपये की वसूली की गई

प्रतिदिन तकरीबन 50 अल्ट्रासाउंड निजी सेंटरों से कराए जाते हैं। पैलानी क्षेत्र के खप्टिहाकलां गांव निवासी उमा दीक्षित ने बताया कि वह अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जिला महिला अस्पताल गई थीं। वहां से उन्हें अस्पताल की ही एक महिला के साथ चिकित्सक ने निजी सेंटर भेजा, वहां पर अल्ट्रासाउंड कराने के नाम पर 700 रुपये की वसूली की गई। आमतौर पर प्राइवेट सेंटरों में अल्ट्रासाउंड करने के नाम पर 700 रुपये वसूले जाते हैं। जो चिकित्सक अल्ट्रासाउंड के लिए निजी सेंटरों में मरीजों को भेजते हैं। उन्हीं चिकित्सक के नाम पर कमीशन की रकम लिख दी जाती है। मालूम हो कि 700 रुपये में कम से कम 350 रुपये चिकित्सक का कमीशन होता है।

प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के तहत महीने में चार दिन 1, 9, 16 और 24 तारीख को प्रसूताओं को निजी सेंटरों में अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जाता है। यह निशुल्क सेवा है। इसके अलावा किसी भी मरीज को निजी सेंटर नहीं भेजा जाता है। इन चार तारीखों के अलावा पहुंचने वाली प्रसूताओं या मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए पुरुष अस्पताल में भेजा जाता है।

बिजली कटौती के विरोध में किसानों ने बिजलीघर पर जड़ा ताला

शामली, संवाददाता। कमालपुर उदपुर के किसानों ने बिजली कटौती से परेशान होकर बिजलीघर में ताला डाल दिया तथा मांगे पूरी न होने तक धरने पर बैठ गए। बिजली घर में तालाबंदी की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता को भी किसानों ने अपने बीच बैठा लिया।

करीब दो घंटे चली वार्ता के बाद मांगे पूरी करने के आश्वासन पर बिजली घर का ताला खोला गया। भीषण गर्मी में बिजली से परेशान कमालपुर, उदपुर और अन्य गांव के किसान इकट्ठा होकर कमालपुर बिजलीघर पर पहुंचे। बिजली कटौती को लेकर किसानों ने बिजलीघर पर तालाबंदी कर दी। तालाबंदी के बाद बिजली कटौती के खिलाफ किसान धरने पर बैठ गए। किसानों की अगुवाई कर रहे किसान मैनपाल ने बताया कि हमारे यहां बिजली सप्लाई बार–बार बाधित होती रहती है। जिससे न तो गर्मी में पंखे आदि चलते हैं और न ही खेतों में पानी की किल्लत को दूर हो रही है। कमालपुर बिजली घर पर मात्र पांच केवीए के दो ट्रांसफार्मर हैं। जिन्हें 10 केवीए का किया जाना चाहिए। 132 केवीए सिकंदरपुर झिंझाना पर केरटू और कमलपुर एक ही ब्रेक पर है। जिन्हें अलग–अलग किए जाने की मांग की।

बालू भरा ट्रक पलटा, आठ लोगों की मौत

हरदोई, संवाददाता। हरदोई जिले में मल्लावां कोतवाली क्षेत्र में उन्नाव मार्ग पर बालू भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया। घटना में झोपड़ी में सो रहे चार मासूम बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दंपती, उनके चार बच्चे और एक दामाद शामिल हैं। एक बच्ची घायल भी है। मल्लावां कस्बे में उन्नाव मार्ग पर चुंगी नंबर दो के पास सड़क किनारे नट बिरादरी के लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं। मंगलवार आधी रात के बाद कानपुर से हरदोई जा रहा बालू भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे अवधेश उर्फ बल्ला की झोपड़ी पर पलट गया।

यमुना में नहाते समय तीन दोस्त डूबे

शामली, संवाददाता। मंगलवार दोपहर यमुना नदी में नहाते समय हरियाणा के जनपद पानीपत निवासी तीन दोस्त डूब गए। समय रहते गोताखोरों ने एक युवक को सकुशल यमुना से बाहर निकाल लिया। जबकि करीब एक घंटे बाद गोताखोरों ने दो युवकों के शवों को यमुना से बाहर निकाला। मृतक 11वीं और 12वीं के छात्र थे। सूचना पर पानीपत से परिजन भी रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे हरियाणा के पानीपत की विद्या नगर कॉलोनी निवासी प्रिंस (20), विकास (18) और शिवा यमुना में नहाने आए थे। तीनों दोस्त हरियाणा की साइड पुल से करीब 700 मीटर पहले यमुना में नहाने लगे। इस दौरान तीनों दोस्त पानी में डूबने लगे। यमुना किनारे प्लेज लगा रहे किसानों ने शोर मचा दिया। मौके पर आए गोताखोरों ने यमुना में छलांग लगा दी। शिवा को समय रहते गोताखोरों ने यमुना से सकुशल बाहर निकाल लिया।

लेकिन प्रिंस व विकास का पता नहीं चला। सूचना पर कोतवाली प्रभारी विरेन्द्र सिंह कसाना मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों की तलाश शुरू कराई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने प्रिंस व विकास के शवों को यमुना से बाहर निकाला। सूचना पर परिजन भी रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस ने दोनों युवकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।

हाईवे पर दो बेटों संग सड़क पार कर रही महिला को वाहन ने मारी टक्कर

मुजफ्फरनगर, संवाददाता। दिल्ली–देहरादून हाईवे के जानसठ बाइपास पर सड़क पार करते समय मीरापुर थाने के गांव केलापुर निवासी मीना (35) व उसके चार साल के बेटे लवदीप की मौत हो गई। महिला का बड़ा बेटा चुन्नू (7) घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। मंगलवार दोपहर एक महिला अपने दो बेटों के साथ जानसठ पुल के पास हरियाणा प्रदेश की बस से उतरने के बाद जानसठ मार्ग पर जाने के लिए सड़क पार कर रही थी। तभी अज्ञात वाहन ने तीनों को टक्कर मार दी। चालक अपने वाहन को लेकर फरार हो गया।

राहगीरों से सूचना पाकर नई मंडी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डाक्टरों ने महिला व उसके छोटे बेटे को मृत घोषित कर दिया। घायल बड़े बेटे को भर्ती कर लिया। उधर, हादसे के कुछ देर बाद महिला के मोबाइल पर किसी की काल आई तो पुलिस ने उसे हादसे की जानकारी दी। तब पुलिस को बताया गया कि महिला मीरापुर थाने के गांव केलापुर निवासी मोनी पत्नी संदीप है। महिला की ससुराल हरियाणा के जींद में है।

वह अपने दोनों बेटों के साथ अपने मायका आने के लिए चली थी। संभवतः जानसठ पुल के पास चौराहे से मीरापुर जाने के लिए बस पकड़ने के लिए सड़क पार कर रही थी। नई मंडी सीओ रुपाली राव ने बताया कि दोनों शव मोर्चरी में रखवा दिए है। तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

पंजाब नेशनल बैंक के करेंसी चेस्ट में निकले नकली नोट

आगरा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के आगरा में एमजी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के करेंसी चेस्ट में दो हजार और पांच सौ के 13 नोट नकली निकले। भारतीय रिजर्व बैंक के दावा प्रबंधक ने बैंक के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। नाई की मंडी थाना प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि आरबीआई के दावा अनुभाग के प्रबंधक आईपीएस गहलोत ने पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड़ से शिकायत की थी। नोट बंदी के दौरान कई बैंकों के करेंसी चेस्ट में नकली नोट जमा हुए। फरवरी में पंजाब नेशनल बैंक से करेंसी चेस्ट आरबीआई में जमा किया गया। जांच में दो हजार और पांच सौ के 13 नकली नोट मिले। मामले में रकाबगंज थाने से मुकदमा नाई की मंडी थाना भेजा गया है। अज्ञात कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

वकील से मारपीट में रेल कर्मचारी का तबादला

बांदा, संवाददाता। अधिवक्ता के साथ मारपीट करने वाले रेल कर्मचारी का तबादला कर दिया गया है। उधर, वकीलों की शिकायत पर जीआरपी की संदिग्ध भूमिका को लेकर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने नगर मजिस्ट्रेट को पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक दीक्षित ने बताया कि एक जून को तत्काल टिकट काउंटर पर रेलवे कर्मचारी (प्वाइंट मैन) धीरेंद्र कुमार यादव ने अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद के साथ अभद्रता व मारपीट की। जीआरपी पुलिस ने रेलवे कर्मचारी के दबाव में समझौता कराकर मामला दबा दिया। शिकायत पर डीआरएम ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी का महोबा तबादला कर दिया है। उधर, वकीलों ने मंगलवार को डीएम को ज्ञापन देकर कहा कि मामले में जीआरपी की भूमिका संदिग्ध थी। जन संपर्क अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि आरोपी रेल कर्मचारी का स्थानांतरण कर चार्जशीट दे दी गई। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

बुखार से दो लोगों की मौत, 12 से अधिक भर्ती

बांदा, संवाददाता। जिला अस्पताल में मंगलवार को बुखार से दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, बुखार और डायरिया से ग्रसित 12 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरका थाना क्षेत्र के पिंडारन गांव निवासी दयाशंकर (70) को तीन जून को रात साढ़े 10 बजे जिला अस्पताल में बुखार के चलते भर्ती कराया गया था, उसकी मंगलवार को दोपहर डेढ़ बजे मौत हो गई। इसी तरह से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजीरा गांव निवासी राजा (45) को नौ जून को भर्ती कराया गया था। 10 जून को उनकी मौत हो गई थी। उधर, शहर के मढिघ्यानाका मोहल्ला निवासी पूजा (25), अतर्रा निवासी भरत मिलन (45), सैमरी गांव निवासी बिंदी (60), बलखंडी नाका मोहल्ला निवासी रूही (2), मटौंध निवासी सुरेश (55), सहेवा गांव निवासी सतेंद्र (8), परई गांव निवासी दशरथ (19), कैरी गांव निवासी रनिया (60), भाथा गांव निवासी राकेश (40), सबादा गांव निवासी अब्दुल रहमान (68), खैराडा गांव निवासी रचना (23), इचौली गांव निवासी मुन्नी (50) को डायरिया व बुखार के चलते भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ ईएमओ डॉ. विनीत सचान ने बताया कि इन दिनों ट्रॉमा सेंटर में 100 से 150 डायरिया के मरीज के आ रहे हैं। इस सीजन में खानपान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर तीन से चार बार दस्त आ रहे हैं तो तत्काल जिला अस्पताल में दिखाएं।

फंदे पर लटकी मिली नव विवाहिता, दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज

सहारनपुर, संवाददाता। गांव बडूली माजरा में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता फंदे पर लटकी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा। मृतका के पिता ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। गांव बडूली माजरा ने सतपाल शर्मा की पुत्रवधू साक्षी (25) पत्नी विशाल सोमवार रात अपने कमरे में सोने गई थी। सुबह जब परिजन उठे तो साक्षी को जगाने के लिए जैसे ही उसके कमरे में गए तो वह चुन्नी से बने फंदे से पंखे पर लटकी थी। घटना की सूचना पुलिस और मायके वालों को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा। परिजनों ने बताया कि साक्षी की शादी इसी साल 19 अप्रैल को विशाल के साथ हुई थी। बताया जाता है कि विवाहिता अभी चार दिन पहले ही मायके से ससुराल आई थी। उसका पति विशाल शर्मा हरिद्वार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। सोमवार सुबह ही वह घर से हरिद्वार के लिए निकला था।

किए ताबड़तोड़ वार, नहीं कांपे हाथ, 500 मीटर दूर फेंका सिर

शामली, संवाददाता। शामली जनपद के चौसाना थानाक्षेत्र के बल्ला माजरा गांव में इमाम फजलू रहमान पर वार करते हुए बेटे जुनैद के तनिक भी हाथ तक नहीं कांपे। न पिता का लाड़ याद आया और न उनका प्यार। यहां तक कि गर्दन को अलग कर सिर को 500 मीटर दूर एक खेत में फेंककर खुद भी छिप गया। मौलवी पिता को साइकिल पर मस्जिद जाना था। उसी साइकिल को लेकर जुनैद खेत में पहुंच गया। पिता फजलू रहमान खेत पर पहुंचे और साइकिल लाने का उलाहना दे दिया। इसी मामूली सी बात पर वह इतना आक्रमक हुआ कि पिता पर फावड़े से तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं हो गई।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।